

2030 तक सात प्रतिशत रहेगी विकास दर

मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, बुनियादी सुविधाओं-डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से यह संभव होगा

जागरण न्यूज़, नई दिल्ली : मुख्य आर्थिक सलाहकार जी. अनंत नागेश्वरन जब मानना है घरेलू और वैश्विक मॉडल को देखते हुए, दशक के अंत तक भारत की विकास दर प्रत्येक वर्ष 6.5-7% रह सकती है। बुनियादी सुविधाओं एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से यह संभव दिख रहा है, लेकिन इसे पाने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग में एसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा।

कारोबार के लिए निवेशों के भार को कम करना होगा और सप्लाय चेन की मजबूती के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। बुधवार को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में नागेश्वरन ने कहा कि इस बार अच्छा मानसून रहने से खुदरा मंहंगाई आरबीआई के अनुमान के मुताबिक चार प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी विकास दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है।



वैश्विक स्थिति बदल रही है और उसे ध्यान में रखते हुए हमें घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा जैसी चीजों पर



-जी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार

फोकस करना होगा। निजी सेक्टर का निवेश भी बढ़ रहा है और घरेलू कचत का पोर्टफोलियो शिफ्ट हो गया है। मालवा बैंक में पैसा जमा करने की जगह लोग रियल एस्टेट, शेयर बाजार जैसी जगहों पर पैसा लगा रहे हैं।

● जी अनंत नागेश्वरन ने कहा-विकास दर बनाए रखने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग में एसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा

● नियमों के भार को कम करना होगा और सप्लाय चेन की मजबूती के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा

जनसंख्या वृद्धि दर कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात

एनसीईआर की महानिदेशक और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) की सदस्य पूनम गुप्ता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक इस साल वैश्विक व्यापार और विकास दर दोनों में कड़ोती होगी जबकि महंगाई में कमी आएगी। वहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत स्थिति में है। इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल और अगले साल सात प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद की जा सकती है। गुप्ता ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात यह है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है जबकि विकास दर बढ़ रही है। 1990 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत थी जो अब एक प्रतिशत हो गई है। सरकारी स्थापित से नीतिगत जोखिम कम हो गया है। बारिश पर कृषि की निर्भरता कम हुई है, विदेशी मुद्रा के भंडार के साथ बैंकों से कर्ज देने की दरों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस मौके पर विश्व बैंक के कंट्री निदेशक अगस्टे टैने ने कहा कि वैश्विक विकास दर अच्छी रही तो भारत की विकास दर आठ प्रतिशत तक पहुंच सकती है।



पूनम गुप्ता ●